प्रेस विज्ञप्ति

बिहार सरकार ने राज्य में आईटी एवं इससे जुड़ी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र विकसित करने का लक्ष्य रखा

राज्य के आईटी मंत्री श्री जिबेश कुमार ने कनवर्जेंस इंडिया को संबोधित किया, राज्य आईटी पार्क और स्टार्टअप पारितंत्र विकसित कर रहा है

नयी दिल्ली, 26 मार्च, 2021: बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य में आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं में भारी निवेश लाने और इसे देश में उभरते हुए आईटी केंद्रों में से एक के तौर पर विकसित करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने की घोषणा की है। बिहार राज्य में आईटी क्षेत्र में निवेश 2017–22 के दौरान साल दर साल 20 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ने की संभावना है। यहां 28वें कनवर्जेंस इंडिया 2021 में बोलते हुए **बिहार के आईटी विभाग के मंत्री श्री जिबेश कुमार** ने सरकार की पहल, इस राज्य में निवेशकों के लिए अवसर पर अंतर्दृष्टि साझा करते हुए कहा कि कैसे इस राज्य ने समावेशी विकास और व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन के लिए आईसीटी की ताकत का दोहन करने की सोच रखी है।

बिहार राज्य परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में तीन आईटी पार्क निर्माणाधीन है जिनमें निर्बाध नेटवर्क संपर्क के साथ बिहटा में 33 एकड़ का आईटी पार्क, राजगीर में 110 एकड़ में तीन चरणों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के विकास के साथ सुस्थापित संपर्क वाला आईटी पार्क और पटना में 90,000 वर्ग फुट के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के साथ आईटी टावर शामिल है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्टअप को सहयोग के लिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में पटना के बीआईटी में एक इनक्यूबेशन सेंटर पहले से ही परिचालन में है।

स्टार्टअप पारितंत्र के लिए बिहार सरकार ने कई पहल की है और राज्य द्वारा अधिसूचित इनक्यूबेशन केंद्रों को 100 प्रतिशत निःशुल्क इनक्यूबेशन का काम 900 से अधिक स्टार्टअप्स को सौंपा जा चुका है। इस राज्य को प्रमाणन के लिए बिहार स्टार्टअप पोर्टल पर 5,591 आवेदन प्राप्त हुए हैं और राज्य सरकार ने 100 से अधिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस राज्य में 104 स्टार्टअप्स का इनक्यूबेशन किया गया है और 53 प्रमाणित स्टार्टअप्स इस राज्य की स्टार्टअप नीति के तहत राजकोषीय लाभ उठा रहे हैं।

कनवर्जेंस इंडिया में बोलते हुए **बिहार के आईटी विभाग के मंत्री श्री जिबेश कुमार** ने कहा, ‘‘मौजूदा सरकार समावेशी और सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य से आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं के उद्योग को विकसित करने के लिए ‘कारोबार सुगम बनाने’ की नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को संकल्पबद्ध है। इस राज्य के पास ढेरों कुशल कर्मचारियों की फौज है जिन्हें बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन प्राप्त है। हमें पक्का विश्वास है कि यह कारोबारी घरानों को लागत घटाने और लाभ बढ़ाने का

अवसर उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में चल रहे प्रयासों के तहत हम विभिन्न नीतिगत एवं नियामकीय सुधार कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि बिहार इस उद्योग के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक होगा।"

राज्य सरकार ने इस राज्य में नवाचार, इनक्यूबेशन और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए पटना में टेक्नोलॉजी इन्नोवेशन एंड इनक्यूबेशन जोन के तौर पर एक स्टार्टअप हब भी स्थापित किया है जहां स्टार्टअप्स को ढांचागत सुविधाएं मिलेंगी, रियासती दर पर गुणवत्तापूर्ण बिजली और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही उन्हें परामर्श, प्रशिक्षण, क्रियान्वयन, इनक्यूबेशन और वैधानिक अनुपालन में जरूरी सेवाएं भी मिलेंगी।

वर्ष 2017 से यह विभाग 20,000 युवाओं को बढ़ते क्रम में रोजगार उपलब्ध कराने और कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के जरिये इस देश में आईटी एवं इससे जुड़े क्षेत्र में अग्रणी स्टार्टअप केंद्रों में से एक के तौर पर उभरने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह सरकार आईटी एवं इससे जुड़े क्षेत्र में 10,000 करोड़ रूपये का सकल कारोबार हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उसका लक्ष्य आईटी एवं इससे जुड़े क्षेत्र में 20 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर से निवेश आकर्षित करना है।

निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक समग्र परिवर्तन हासिल करने के लिए यह सरकार कारोबारी नियमन के सभी संबंधित क्षेत्रों में नियामकीय सुधारों को गति दे रही है। बिहार सरकार इस राज्य में आईटी एवं इससे जुड़ी परियोजनाओं के आवेदनों को तेजी से आगे बढ़ाने और बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के तहत प्रोत्साहन की मंजूरी एवं वितरण के लिए समयबद्ध एकल खिड़की मंजूरी के प्रावधान सुनिश्चित कर रही है। राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत निवेशकों की सुविधा के लिए एक **निवेशक सुविधा सह परियोजना प्रबंधन इकाई** स्थापित की है।

बिहार सरकार के आईटी विभाग के बारे में

वर्ष 2007 में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी संचालित सेवाओं के इस्तेमाल के लिए इस राज्य के अन्य विभागों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। इस विभाग का लक्ष्य बिहार को आईटी एवं इससे जुड़े उद्योग के लिए एक आकर्षक स्थल के तौर पर स्थापित करना, ई गवर्नेंस एवं एम गवर्नेंस के जरिये नागरिक सेवाएं बढ़ाना और राज्य में स्टार्टअप्स एवं उदीयमान उद्यमियों को फलने फूलने के लिए उन पर विशेष ध्यान देना है। यह विभाग ई गवर्नेंस में गहराई से काम कर रहा है। बीएएएफ–आधार आधारित लेनदेन की रूपरेखा, सीएफएमएस, एचआरएमएस आदि मौजूदा एप्लीकेशंस हैं जिनका उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है। वहीं बी–स्वान और बिहार क्लाउड, एकीकृत आईटी सुविधा वाले आधारभूत ढांचे हैं। स्टेट डेटा सेंटर–अत्याधुनिक टियर 3 डेटा सेंटर पहले से ही परिचालन में है।

अन्य जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें–

Ashwani Gupta/ Rabindra Jha
Phone: 9818745476 / 9899235055